इकाई 7 पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एवं समाज

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 आर्थिक विकास

- 7.2.1 आरम्भिक वर्ष: आजीविका के लिए संघर्ष
- 7.2.2 अयूब का विकास दशक
- 7.2.3 भुट्टो का समाजवाद के साथ प्रयोग
- 7.2.4 ज़िया की सैनिक सरकार
- 7.2.5 लोकतंत्र की वापसी एवं संरचनात्मक समायोजन (1988-98)
- 7.2.6 नई सहस्त्राब्दि में अर्थव्यवस्था
- 7.2.7 संरचनात्मक परिवर्तन

7.3 सामाजिक विकास

7.4 पाकिस्तानी समाज

- 7.4.1 भाषायी समूह
- 7.4.2 संजातीय समूह
- 7.4.3 धर्म

7.5 सारांश

7.6 शब्दावली

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस अध्याय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज की चर्चा की जाएगी। इसे पढ़ने के बाद आप:-

- विभिन्न शासनकालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों का पता लगा पाएँगे;
- पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों पर टिप्पणी कर पाएँगे;
- पाकिस्तान के विकास के सामाजिक पहलुओं को जान पाएँगे; और
- पाकिस्तान के समाज की प्रकृति, इसकी भाषायी, संजातीय और धार्मिक विशेषताओं का मूल्यांकन कर पाएँगे।

7.1 प्रस्तावना

पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का दूसरा बड़ा देश है। इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण की ओर 1500 कि० मी० तथा चौड़ाई औसतन 450 कि० मी० है जिससे इसका आकार उत्तर में यामिर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक आयताकार हो जाता है। उत्तर में हिमालय की उच्च पर्वतीय

श्रृंखला, हिन्दूकुश तथा काराकोरम देश को चीन, केन्द्रीय एशियाई देशों तथा अफगानिस्तान से अलग करती है। पाकिस्तान के पश्चिम में दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान तथा पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के भारतीय राज्य हैं। अरब सागर जोकि देश को प्रमुख सागर धारा से जोड़ता है, वह देश की दक्षिणी सीमा का कार्य करता है।

पाकिस्तान कई रूपों तथा भौगोलिक विविधताओं का देश है। देश की प्राकृतिक विशेषताएँ लगभग 100 कि० मी० पर बदल जाती हैं। यहाँ दक्षिण में समुद्री तट, समुद्रताल, कच्छ वनस्पति है तो केन्द्रीय क्षेत्र में मरूस्थल, विच्छिन्न पठार, उपजाऊ मैदानी भाग तथा विरदित उपजाऊ भूमि है तो उत्तरी क्षेत्र ऊंचे पर्वतों से घिरा है।

जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का तीसरा बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या में पांच प्रमुख संजातीय समूह हैं - पंजाबी, पश्तुन, सिंधी, बलूची तथा मुहाज़िर अथवा उत्तर भारत से विस्थापित लोग।

पाकिस्तान को प्रमुखत: कृषि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। नए राष्ट्र के गठन के समय देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती थी, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में यह अधिक कृषि प्रधान थी। पाकिस्तान के पास खनिज संसाधनों के भंडार नहीं थे तथा आधुनिक फैक्टरी उद्योग लगभग न के बराबर था। तब से लेकर पाकिस्तान ने उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा उच्च वृद्धि दर रिकार्ड की गई है परन्तु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिकांश वृद्धि कृषि क्षेत्र की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र के कारण हुई है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के अनुपात में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास का लाभ क्षेत्र तथा वर्ग की दृष्टि से सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला है जिसके कारण पाकिस्तान एक असमान समाज रहा है।

पाकिस्तान की पहली चुनी गई असैनिक सरकार यानी जुल्फीकार अली भुट्टो के शासनकाल के दौरान इन असंतुलनों को ठीक करने के प्रयास किए गए परन्तु इससे पहले कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो सकती, पाकिस्तान में पुन: सैनिक शासन स्थापित हो गया। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के डावांडोल राजनीतिक इतिहास ने देश के आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न की हैं अथवा विकास की गति को धीमा किया है। इस अध्याय में हम अलग-अलग राजनीतिक शासनों के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक नीति तथा नियोजन की जांच करेंगे ताकि प्रत्येक शासनकाल में प्रबलित नीति क्षेत्र तथा आर्थिक प्रगति पर बाहय पर्यावरण के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

7.2 आर्थिक विकास

जब 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ तो इसे लगभग नए सिरे से शुरूआत करनी पड़ी। पाकिस्तान के अन्तर्गत आया क्षेत्र अधिकांशत: कृषि तथा पिछड़ा क्षेत्र था तथा इस पर कुछ सामन्ती ज़मींदारों का आधिपत्य था। इसे जो थोड़े-बहुत उद्योग विरासत में मिले वे हस्तकलाओं अथवा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर आधारित थे और फिर देश के उद्योग तथा व्यापार पर हिन्दुओं तथा सिक्खों का अधिकार था जो विभाजन के तत्काल बाद अपनी पूंजी के साथ देश छोड़कर चले गए। पश्चिमी पाकिस्तान के व्यावसायिक कार्यकलापों का प्रबंधन काफी हद तक इन समुदायों के हाथ में था। अत: उनके चले जाने से इन प्रमुख क्षेत्रों में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई।

पाकिस्तान की आरम्भिक समस्याएँ बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से और बढ़ गईं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विभाजन के बाद पहले तीन वर्षों के दौरान लगभग एक करोड़ 20 लाख लोग भारत से पाकिस्तान में आए।

उप-महाद्वीप के विभाजन से क्षेत्र के सम्पूरकता के सिद्धान्त को धक्का पहुँचा। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान में सदैव उपभोग से अधिक गेहूँ का उत्पादन होता था तथा इसे भारत में गेहूँ की कमी वाले क्षेत्रें को भेजा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान में बोई जाने वाली कपास का इस्तेमाल बम्बई तथा अन्य पश्चिम भारतीय शहरों की मिलों में किया जाता था। निर्मित उत्पाद जैसे कोयला और चीनी उन क्षेत्रें में कम थे जो पाकिस्तान के अन्तर्गत थे तथा इन्हें वर्तमान भारत के हिस्से से मंगाया जाता था।

प्रशासनिक मशीनरी, भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भी विभाजन की समस्या थी। कुल 1157 अधिकारियों में से केवल 157 पाकिस्तान की सिविल सेवा में शामिल हुए जो विश्व में सर्वाधिक अभिजातवर्गीय और विशेषाधिकार प्राप्त नौकरशाही सेवाओं में से एक बन गई।

नए राज्य के लिए एक सुखद बात थी - ब्रिटिश शासन काल के दौरान का पर्याप्त सिंचाई नेटवर्क। विभाजन के समय अधिकांशत: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं जैसे सड़कों, बिजली, रेल पटरियों इत्यादि की अपर्याप्तताओं के मद्देनजर उपयुक्त सिंचाई प्रणाली देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक साधन थी।

7.2.1 आरम्भिक वर्ष : आजीविका के लिए संघर्ष

आरम्भिक वर्षों में (1947-58) पाकिस्तान की आर्थिक नीति तथा नियोजन पर थोड़े से नौकरशाहों का वर्चस्व था। विभाजन के समय की बदहाल परिस्थितियों के मद्देनजर आर्थिक नियोजन का एक सूत्री कार्यक्रम था किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाना। देश में चूंकि निजी क्षेत्र कमजोर था तथा औद्योगिक विकास आरम्भ करने के लिए उसके पास पूंजी का अभाव था, अत: देश में आर्थिक आधर स्थापित करने का मुश्किल कार्य राज्य को सौंपा गया।

1947-58 के आर्थिक नीति विश्लेषण से विकट स्थितियों में तदर्थ प्रतिक्रियाओं के क्रम का पता चलता है। पाउंड स्टरलिंग के अवमूल्यन तथा भारत द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के बाद पाकिस्तान से ऐसा करने के लिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया जिसके कारण भारत के पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों में कड़वाहट आ गई किन्तु 1952 का कोरियाई युद्ध पाकिस्तान के लिए वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि इससे पाकिस्तानी निर्यात, अधिकांशत: पटसन और कपास की मांग बढ़ गई जिससे नवजात उद्यम वर्ग को विकसित होने में सहायता मिली। इसी अप्रत्याशित आय की बदौलत पाकिस्तान में उद्योग की नींव रखी गई।

कोरियाई मांग की समाप्ति पर पाकिस्तान के प्रतिकूल रोष के कारण भुगतान समस्या के प्रबंधन के लिए तैयार की गई आयात लाईसेंस प्रणाली में आई जटिलताओं के कारण इसकी पुन: जांच की गई। प्रशासनिक तथा लाइसेंस नियंत्रण का जटिल नेटवर्क ही बाद में पाकिस्तान की आयात सम्पूरक रणनीति का आधार बना।

अत: स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में मूलत: नौकरशाहों का वर्चस्व रहा तथा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। चूंकि अधिकांश नौकरशाह भारत के शहरी क्षेत्रों से गए लोग थे, अत: उन्हें कृषि क्षेत्र का इतना न तो ज्ञान था और न ही रूचि थी और उन्होंने यह महसूस किया कि निर्माण क्षेत्र को राज्य का अधिक से अधिक संरक्षण दिया जाए। बड़े-बड़े ज़मीदार तथा नवाब जिन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, इसे आर्थिक स्तर पर समर्थन में परिवर्तित नहीं करा सके जबकि कुछेक उद्योगपतियों को आरम्भिक वर्षों में आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ परन्तु उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं था, वे सिविल अधिकारियों के लाइसेंस राज पर निर्भर थे। मौजूदा राजनीतिक समूहों के पदों में अव्यवस्था के कारण सेना ने कानून एवं व्यवस्था बहाल करने तथा 1950 के दशक के दौरान उभरे नौकरशाही पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कदम रखा।

7.2.2 अयूब का विकास दशक

जनरल मौहम्मद अयूब खान का शासन पाकिस्तान इतिहास में अति उल्लेखनीय वृद्धि दर का विवादास्पद और विरोधाभासपूर्ण संगम था जिसके दौरान आय में असमानता, अन्तर्क्षेत्रीय विषमता में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई तथा आर्थिक शक्तियाँ सिमटकर कुछेक हाथों में आ गईं।

इस दशक के दौरान आर्थिक सूचक भी अत्यंत प्रभावशाली रहे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पूरे दशक के दौरान 6 प्रतिशत के आसपास रही। पूरी अवधि में कृषि विकास दर सम्मानजनक 4.1 प्रतिशत रहा जबकि निर्माण क्षेत्र में विकास दर 9.1 प्रतिशत और व्यापार में 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई किन्तु आय के वितरण, मजदूर एवं मानव पूंजी विकास के आंकड़े निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आय की असमानता के सूचकांकों में और गिरावट आई तथा निर्धन और निर्धन हो गए। अधिकांश जनसंख्या के जीवनस्तर में स्थिरता आ जाने से मजदूरी में वृद्धि का लाभ उत्पादकता में वृद्धि के रूप में नहीं मिल सका।

अयूब की आर्थिक नीतियों का प्रमुख मुद्दा था - तीव्र औद्योगिकीकरण के प्रति वचनबद्धता। नीति निर्माण औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत निवेश लाइसेंस और क्रेडिट निपटान की योजना और प्रक्रिया बनाई गई। इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम (पी आई डी सी) का गठन किया गया जिससे अत्यंत अनिवार्य पूंजी उपलब्ध कराई गई तथा तब बाद में निजी क्षेत्र, जिसमें वृहत परियोजनाएँ चलाने के लिए कौशल तथा वित्त का अभाव था, को बढ़ावा देने के लिए इसे वापस ले लिया गया। जैसे-जैसे औद्योगिक लाभ बढ़ते गए, उद्यमी वर्ग का जन्म हुआ जिसने इस दशक के दौरान बड़े निर्माण क्षेत्र में विकास दर को 15 प्रतिशत से अधिक तक ले जाने में योगदान दिया।

अयूब के शासन काल के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुधार किए गए। 1959 के भूमि सुधार कार्यक्रम प्रमुख ज़मीदार वर्ग के एकाधिकार को समाप्त करने के साथ-साथ पूंजीवादी कृषि विकास को बढ़ाने देने के उद्देश्य से चलाए गए।

इसके बाद साठ के दशक के मध्य के वर्षों के दौरान हरित क्रान्ति आई। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत धान तथा गेहूँ की उच्च उपजशील किस्में आईं। मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकीकरण विस्तार के माध्यम से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। निजी ट्यूबवैलों के लगने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग का भी कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान रहा। हालांकि कृषि क्षेत्र में तीव्र मशीनीकरण के कारण छोटे किसानों को काम नहीं मिला और इस प्रकार से ग्रामीण असमानता और बढ़ गई।

इस प्रकार से अयूब के वर्षों की मिली-जुली विशेषताएँ इस प्रकार रहीं। एक तरफ तो आर्थिक प्रबंधन में मजबूती तथा उच्च विकास दर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रहीं तो दूसरी ओर आय असमानता में वृद्धि, मजदूरी में स्थिरता, मानव पूंजी की उपेक्षा तथा विदेशी पूंजी निर्भरता बढ़ने से निश्चित रूप से वे चुनौतियाँ बढ़ीं जिनका सामना भावी शासकों को करना पड़ा।

7.2.3 भुट्टो का समाजवाद के साथ प्रयोग

वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया तथा भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर जुल्फीकर अली भुट्टो ने देश की बागडोर संभाली, जो तत्कालीन करिश्माई चुना गया नेता था जिसने समाजवादी सिद्धान्तों पर देश के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र को पुनः ढांचागत करने के प्रयास किए। पहली बार देश की सेना तथा नौकरशाही पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के प्रयास किए गए। पिछले दशक के सामाजिक तथा आर्थिक असंतुलनों को संतुलित करने के भी प्रयास किए गए।

भुट्टो ने नई विकास नीति लागू करने का वचन दिया जो पिछली नीतियों की तुलना में समानता के अधिकार पर आधारित थी। देश की सत्ता संभालने के बाद भुट्टो प्रशासन का प्रमुख निर्णय

1972 में रूपये का 57 प्रतिशत तक अवमूल्यन करना तथा बहु विनिमय दरों को हटाना था। इससे पाकिस्तान के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के कारण व्यापार में हुई क्षति की भरपाई नए बाजारों की प्राप्ति के रूप में हुई।

भुट्टो शासन क सबसे क्रान्तिकारी निर्णय बड़ी निजी निर्माण तथा वित्तीय संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण था। 1972 में सभी निजी बैंकों तथा बीमा कम्पनियों और 8 प्रमुख उद्योगों के 32 बड़े निर्माण प्लांटों का राष्ट्रीयकरण धन के कुछेक हाथों में एकत्र होने को रोकने और निजी उद्योगपतियों की शक्तियों का कम करने के उद्देश्य से किया गया। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन आया तथापि वृहत निर्माण क्षेत्र में, विशेषकर कपड़ा तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण क्षेत्र में, गुणवर्द्धन का लगभग 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र के पास रहा।

राष्ट्रीयकरण के परिणाम आशाजनक नहीं निकले क्योंकि इस अवधि में योग्य प्रबंधकों तथा तकनीकीविदों की कमी के कारण, जिनमें से अधिकांश उच्च वेतन के लालच में मध्य पूर्व के देशों में चले गये थे, वृहत राष्ट्रीकृत क्षेत्र तेजी से कार्य नहीं कर पाया।

निजी पूंजी देश से बाहर अथवा छोटे पैमाने के निर्माण अथवा वास्तविक सम्पदा क्षेत्र में चली गई। इसका एक अनुकूल परिणाम यह निकला कि इससे छोटे पैमाने के निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही जबकि बड़े पैमाने के उप-क्षेत्र में यह वृद्धि 4.2 प्रतिशत थी। इस अवधि में औद्योगिकीकरण का एक अन्य लाभ यह हुआ कि पहली बार देश में इस्पात, उर्वरक तथा रसायन जैसे आधारभूत उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए गए जिससे भावी विकास की नींव रखी गई और जिसका लाभ बाद के शासकों को मिला।

इस दशक के अधिकांश समय में कृषि विकास की दर बाह्य तथा नीतिगत कारणों से कम रही। प्रथम, जलवायु संबंधी परिवर्तनों तथा विषाणु रोगों ने फसलों को प्रभावित किया, विशेषकर कपास उत्पादन के क्षेत्र में अत्यंत क्षति हुई। दूसरे, उच्च उपजशील किस्मों से उत्पादकता का लाभ प्राप्त करते रहने के लिए अनिवार्य प्रमुख कृषि निवेश पदार्थों जैसे जल और उर्वरक की आपूर्ति में कुल मिलाकर कमी रही।

भुट्टो के शासन काल में पाकिस्तान के बाह्य क्षेत्र से संबंधित नकारात्मक प्रवृत्ति बनी - भुगतान शेष का बढ़ना तथा उसके परिणामस्वरूप देश के बाह्य ऋणों में वृद्धि। इन वर्षों के दौरान भुट्टो की नीतियों के कारण धन प्राप्ति अधिक रही जिससे देश की बाह्य निर्भरता बढ़ गई।

इस अवधि के दौरान पाकिस्तान में आर्थिक विकास की गति अत्यंत कम रही जिसका कारण बाह्य परिवर्तन थे जिनसे बड़े पैमाने पर उल्लेखनीय आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बन गई। सर्वप्रथम तो विनाशक गृह युद्ध के उपरान्त पूर्वी पाकिस्तान के अलग हो जाने से अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में कमी आई। दूसरे, 1970 के दशक में नव गठित ओपेक (OPEC) मूल्य निर्धारक सभा की नीतियों के कारण तेल संकट बना रहा। तीसरे, 1970 के दशक में पाकिस्तान की निर्यात जिन्सों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में पर्याप्त उतार चढाव आया। अंत में, खराब मौसम, बाढ़ें तथा कीटों के हमले से कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई।

7.2.4 ज़िया की सैनिक सरकार

संयोग से यह अवधि जनरल ज़िया-उल-हल के सैनिक शासन की भी थी जिसने राजनीतिक स्थिरता की पुनर्स्थापना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा समाज के इस्लामीकरण के उद्देश्य से सत्ता अपने हाथ में ली।

1970 के दशक के बिल्कुल विपरीत 1980 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान विकास नीतियों को बदला गया। इस अवधि में अस्थिरता लाने वाले बाह्य कारणों की कमी रही। परिणामस्वरूप, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से अधिक रही। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर

भुट्टो के शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में हुए निवेश, विशेषकर भारी उद्योगों में हुए निवेश तथा घरेलू मांग में तीव्रता से आई वृद्धि के कारण हुई।

1979 में अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पर्दे पर पाकिस्तान दृष्टिगोचर हुआ जिससे न केवल उसके शासन को राजनीतिक वैधता मिली अपितु पर्याप्त विदेशी सहायता और युद्ध संबंधी सहायता के साथ-साथ मुद्रा का बहाव देश में होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। अफगान युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20-30 प्रतिशत के अनुपात पर अनुमानित समानान्तर तथा अवैध अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया।

1980 के दशक में पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई जो लगभग दशक के अधिकांश समय में लगभग 3 बिलियन डालर प्रति वर्ष थी। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत तथा चालू लेखा प्राप्तियों का 45 प्रतिशत थी। बाहर से प्राप्त राशि के कारण घरेलू आय में वृद्धि हुई और निवेश के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण निजी क्षेत्र में निवेश किया गया।

फिर भी 1980 के दशक में देश में वित्तीय घाटा बढ़ा जो 1980 के उतरार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत रहा। इससे 1990 के दशक के दौरान सार्वजनिक निवेश तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़े।

औद्योगिक दृष्टि से ज़िया-उल-हक़ के शासन काल में अर्थव्यवस्था को विनियमित तथा उदारीकृत किया गया ताकि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। 1980 के दशक में सरकार की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं रहीं - कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का विराष्ट्रीयकरण, निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन के पैकेज का प्रावधान तथा विनियामक नियंत्रणों का उदारीकरण।

इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि तथा मध्यवर्ती व मशीन उद्योगों में विकास से पाकिस्तान के उद्योगों का विविधीकरण हुआ।

1980 के दशक में बाजार तथा उत्पादन के विनियमन से पाकिस्तान की कृषि में उल्लेखनीय ढांचागत परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दृष्टि से लाई गई नीतियों में शामिल थे - चीनी, कीटनाशक तथा उर्वरक उद्योगों का विनियमन, धान एवं कपास निर्यात निगमों के एकाधिकार की समाप्ति तथा निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य तेलों के आयात पर लगी रोक को हटाना। कीटनाशकों तथा उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता हटाने से कीमत प्रणाली अधिक बाजारपरक हो गई।

कुल मिलाकर इस अवधि में पर्याप्त समष्टि आर्थिक स्थिरता आई तथा निजी निवेश में फिर से वृद्धि हुई परन्तु बढ़ता हुआ व्यापार तथा बजट घाटा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के शुभ सूचक नहीं थे।

7.2.5 लोकतंत्र की वापसी तथा ढांचागत समायोजन : 1988-1998

1988 में जनरल ज़िया-उल-हक़ की मृत्यु के पश्चात देश में लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली हुई। अगस्त, 1988 तथा अगस्त 1997 के बीच पाकिस्तान में चार आम चुनाव हुए जिनमें बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ ने दो-दो बार सत्ता संभाली। चुनी गई कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी।

बजट घाटे को पूरा करने के लिए 1980 के दशक के दौरान अत्यधिक गैर-बैंक ऋण लेने से ऋण लेने तथा चुकाने की प्रक्रिया के कारण 1990 के दशक मे कुल ब्याज भुगतान कुल व्यय का एक तिहाई हो गया। निरन्तर बढ़ते घाटे और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के कारण, जोकि 1990 के दशक में औसतन 6.8 प्रतिशत रहा, अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अन्य विकासशील देशों की तुलना में न केवल वित्तीय घाटा अधिक था, साथ ही घरेलू ऋण की विवशताओं तथा रक्षा परिव्यय के कारण व्यय में कटौती न किए जा सकने के कारण चालू व्यय को कम करने के कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो सके।

हालांकि प्रमुख राजनीतिक दलों - पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तथा मुस्लिम लीग में आधारभूत आर्थिक नीतियों पर सहमति थी किन्तु कार्यक्रमों तथा नीतियों की निरन्तरता नहीं बनी रह सकी। आर्थिक नीतियों पर सर्वसम्मति का लाभ प्रशासनिक तदर्थता तथा नीतियों में उलट फेर के कारण नहीं उठाया जा सका। बल्कि दोनों विरोधी राजनीतिक दल इन नीतियों का उपयोग राजनीतिक सत्ता तथा सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए करते रहे।

इस अवधि में व्यापार के क्षेत्र में कई सुधार लाए गए। 1990 के दशक में कई नीतियाँ लाई गईं जिनसे नकारात्मक सूची (Negative List) के अन्तर्गत मदें कम हो गईं, औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए तथा विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। उद्योग क्षेत्र में विनियमन, उदारीकरण तथा निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1990 के दशक में कई नीतियाँ लाई गईं। इसके साथ-साथ अतिरिक्त, वित्तीय प्रोत्साहन, कर में छूट, निवेश क्षेत्रों में लाइसेंस समाप्त करने तथा पूंजी पदार्थों पर शुल्क घटाने से निजी निवेश को बढ़ावा मिला किन्तु वित्तीय दमन तथा पारदर्शिता में कमी के कारण निजीकरण के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया धीमी रही।

1990 के दशक के दौरान कृषि निष्पादन कम रहा। 1991 तथा 1993 के दौरान अत्यधिक बाढ़ आने तथा कीटों के हमले से कपास के उत्पादन में कमी आई, इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की मौसम की अनिश्चितताओं तथा एक ही नकदी फसल पर निर्भरता की पोल खुल गई।

निष्कर्ष रूप में, पाकिस्तान में आर्थिक विकास में कई कारणों से कमी आई जिसमें समष्टि आर्थिक पर्यावरण को ह्रास, स्थिरीकरण नीतियों तथा ढांचागत सुधारों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियों, कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी स्थितियाँ, अनियमित नीतियाँ एवं अभिशासन की कमियाँ शामिल हैं। 1980 के दशक में 6.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की तुलना में 1980 के पूर्वार्द्ध में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर का औसत घटकर 4.9 प्रतिशत तथा उतरार्द्ध में 4 प्रतिशत रह गया। बाह्य क्षेत्र तथा विशेषकर ऋण प्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था घने दबाव में आ गई। वित्तीय तथा चालू खातें के संचयी असंतुलन के साथ-साथ प्रमुख संस्थानों के ह्रास तथा अभिशासन की कमियों ने उदार आर्थिक नीतियों के शासन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है।

7.2.6 नई सहस्राब्दि में अर्थव्यवस्था

12 दिसम्बर 1999 को चौथी बार देश में तब सैनिक शासन स्थापित हुआ जब सेना प्रमुख, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता-पलट में देश का प्रशासन अपने हाथ में लिया।

जब सेना ने देश की सत्ता संभाली तो पाकिस्तान में सब कुछ अस्त-व्यस्त था। घाटे के भुगतान को पूरा करने की बाध्यताओं के कारण देश भारी विदेशी ऋणों पर निर्भर था, कुल बजट का 56 प्रतिशत ऋण के भुगतान के रूप में जा रहा था। देश पर कुल बाह्य ऋण की राशि 39 बिलियन अमरीकी डालर थी जबकि देश के पास कुल विदेशी विनिमय भंडार केवल 1.45 बिलियन डालर के थे। कर से धन इकट्ठा होना कम हो गया था जबकि वित्तीय घाटा वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.45 प्रतिशत हो गया था।

पाकिस्तान का सकल घरेल उत्पाद वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में क्रमश: 2.2 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत ही था। यह वृद्धि दर पाकिस्तान के दर्ज इतिहास में सबसे कम थी।

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर सैनिक शासन वित्तीय घाटे को 1990 के दशक के 6.1 प्रतिशत की तुलना में कम लाकर 5.6 प्रतिशत करने में सफल रहा है लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि वित्तीय घाटे में हुई कटौती का 40 प्रतिशत सार्वजनिक निवेश में तीव्र कमी लाने से ही संभव हो पाया है।

इस सहस्राब्दि के पहले दो वर्षों में कृषि का निष्पादन सर्वाधिक निराशाजनक रहा है। पहले दो वित्तीय वर्षों में कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर क्रमश: 2.64 प्रतिशत और 0.07 प्रतिशत दर्ज की गई। इतने खराब प्रदर्शन का सबसे प्रमुख कारण भीषण सूखे की अवस्थाओं की वजह से सिंचित जल की कमी है।

मुशर्रफ़ द्वारा देश की सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान पर विदेशी ऋण न चुका पाने का खतरा बढ़ता जा रहा था परन्तु तभी 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ जिससे पाकिस्तान एक ऐसे अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया जो तालिबान तथा अल-कायदा आंदोलन के विरूद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका का सहयोग कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बिलियन अमेरिकी डालर की सहायता दी जबकि पेरिस क्लब से मिली धनराशि से पाकिस्तान के बाह्य ऋणों को काफी हद तक पुन: ढांचागत तथा पुन: निर्धारित किया जा सका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने पर 1998 के मध्य में लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटा लिया।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ी है साथ ही कृषि तथा बड़े निर्माण क्षेत्रें का निष्पादन प्रभावशाली रहा है। यद्यपि पानी की कमी समस्या बनी रही तथापि इसकी कमी का कम प्रभाव पड़ा। प्रमुख फसलों के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ। समग्र रूप से निर्माण क्षेत्र में विकास 7.7 प्रतिशत की दर से हुआ।

बोध प्रश्न 1

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) पाकिस्तान में भारी उद्योगों की नींव कब रखी गई?

.....

.....

.....

2) भुट्टो के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक विकास की गति धीमी होने के क्या कारण थे?

.....

.....

.....

3) 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक नीति में किस क्षेत्र पर प्रमुख बल दिया गया था?

.....

.....

.....

7.2.7 संरचनात्मक परिवर्तन

समय के साथ-साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949-1950 में पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में पश्चिमी पाकिस्तान की कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 53 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र का 7.8 प्रतिशत तथा खुदरा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र का 39.0 प्रतिशत योगदान था। 1996-1997 तक कृषि का योगदान केवल 24 प्रतिशत रह गया जबकि निर्माण का 26.4 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का 49 प्रतिशत हो गया। कृषि में श्रम का प्रतिशत 1990-1991 में 65.3 प्रतिशत था जो 1994-1995 में घटकर 46.8 प्रतिशत

रह गया। इस अवधि के दौरान निर्माण क्षेत्र में श्रम का प्रतिशत 9.5 से बढ़कर 18.5 तथा सेवा क्षेत्र व व्यापार में कार्यरत श्रम का प्रतिशत 25.2 से बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गया। शहरीकरण की दृष्टि से 1951 में पश्चिमी पाकिस्तान के केवल 17 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रें में रहते थे जिनका प्रतिशत नब्बे के दशक तक बढ़कर 40 हो गया।

7.3 सामाजिक विकास

आमतौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के सामाजिक विकास सूचक देश के आर्थिक विकास के अनुरूप नहीं रहे। 1999 में पाकिस्तान की साक्षरता दर केवल 46.4 प्रतिशत थी (58.3 प्रतिशत पुरूष तथा 33.5 प्रतिशत महिलाएँ)। इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा में नामांकन का अनुपात 56.4 प्रतिशत था (पुरूष 64.5 प्रतिशत, महिलाएँ 47.7 प्रतिशत)। पाकिस्तान के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2001 में पाकिस्तान की बाल मृत्यु दर 84/1000 थी तथा पांच वर्ष से कम आयु के लिए 109/1000 थी। 3.8 की जनसंख्या दर तथा 61 वर्ष की जीवन प्रत्याशा से पाकिस्तान की अल्पविकसित तथा जनसांख्यिकीय वृद्धि का पता चलता है। 2001 में पाकितान की जनसंख्या 136.3 मिलियन थी जिसमें से 70.6 मिलियन पुरूष तथा 65.7 मिलियन महिलाएँ थीं जिससे 100 महिलाओं पर 108 पुरूषों के अनुपात से लिंग असंतुलन का पता चलता है। विकास की उच्च दर की अवधियों के दौरान भी पाकिस्तान के निर्धन वर्ग को इसका लाभ नहीं मिला। 1964 में जनसंख्या के 40.2 प्रतिशत का आकलन निर्धन के रूप में किया गया। 1987-88 में यह प्रतिशत कम होकर 17.3 प्रतिशत हो गया परन्तु फिर इसमें बढ़ोतरी हुई। कुछ आकलनों के अनुसार, 2000-2001 में निर्धनता का स्तर 1964 के 40.1 प्रतिशत तक पहुंच गया था अत: निर्धनता के अनुपात की दृष्टि से आज देश वहाँ पहुँच चुका है जहाँ यह चार दशक पहले था। वर्तमान में जनसंख्या की उच्च दर के मद्देनजर इसका अर्थ यह हुआ कि पहले की अपेक्षा आज निर्धनों की संख्या अधिक है।

असमानता की दृष्टि से भी पाकिस्तान की स्थिति निराशाजनक है। 1963-64 से आरम्भ होकर चार दशकों से देश की कुल आय में जनसंख्या के निम्नतम 20 प्रतिशत की आय का प्रतिशत 6.4 से मामूली बढ़कर 1998-1999 में 6.6 प्रतिशत हुआ, जबकि मध्य वर्ग के 60 प्रतिशत की आय 48.3 प्रतिशत से घटकर 45.6 प्रतिशत रह गई परन्तु सर्वाधिक उच्च आय वर्ग के 20 प्रतिशत का कुल आय में हिस्सा 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 47.8 प्रतिशत हो गया।

इसी प्रकार से 1980 के दशक से पाकिस्तान की बेरोजगारी की दर में भी प्रतिकूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। 1981-90 के दौरान यह बढ़कर औसत 3.5 प्रतिशत, 1991-2000 के दौरान 5.7 प्रतिशत तथा 2000-2001 में 6.7 प्रतिशत हो गई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा विश्व बैंक के तत्वाधान में 1988-89 में आरम्भ हुए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के कारण बजटीय तथा चालू लेखा घाटे और कई क्षेत्रीय कार्यक्रमों को कम करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया से निर्धन न केवल इस समायोजन का सबसे बड़ा शिकार हुए हैं अपितु खराब सामाजिक विकास सूचकों से दृष्टिगोचर होता है कि नीति प्रक्रिया का भी उन पर प्रभाव पड़ा है।

7.4 पाकिस्तान में समाज

7.4.1 भाषायी समूह

भाषा संजातीय अभेदवाद का महत्वपूर्ण मार्कर है। पाकिस्तान में 20 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमे से प्रमुख हैं पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू। इसके अतिरिक्त पख्तु (अथवा पश्तु), बलूची

भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार की भारतीय-आर्य शाखा से संबंधित हैं। कुछ अन्य भाषाएँ भारतीय-यूरोपीय तथा प्रारम्भिक द्राविड़ भाषा परिवारों की "दार्दी' शाखा से संबंधित है। ब्राहुई एक ऐसी भाषा है जो बलूचिस्तान के एक वर्ग द्वारा बोली जाती है।

लगभग आधे पाकिस्तानी (48 प्रतिशत) पंजाबी बोलते हैं इसके बाद सिंधी (12 प्रतिशत), पंजाबी का एक रूप सिराइकी (10 प्रतिशत), पख्तु अथवा पश्तु (8 प्रतिशत), बलूची (3 प्रतिशत), हिंदको (2 प्रतिशत) तथा ब्राहुई (1 प्रतिशत) बोली जाती हैं। 8 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी, बुरूशास्की तथा कई अन्य बोलियों सहित अन्य भाषाएं हैं।

भारतीय उप-महाद्वीप के मुसलमानों ने लम्बे समय से यह अनुभव किया है कि उर्दू उनकी सम्मिलित पहचान का सूचक है। इस भाषा ने शिक्षित मुसलमानों के बीच कड़ी का काम किया है। मुस्लिम लीग ने नए राज्य पाकिस्तान को अपनी अलग पहचान देने के लिए उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। हालांकि देशी भाषा के रूप में यह जनसंख्या के केवल 8 प्रतिशत की भाषा थी। शिक्षित पृष्ठभूमि वाले महत्वाकांक्षी लोगों ने उर्दू बोलनी आरम्भ कर दी पर चूंकि अंग्रेजी अधिकांश अभिजात वर्ग की भाषा थी, वस्तुत: अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा बन गई। देश की लगभग आधी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में प्रमुखत: लोक कहानियाँ और रोमांचक लेखन है। यद्यपि पंजाबी मूलत: गुरूमुखी लिपि में लिखी गई परन्तु पंजाबी का, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, उर्दू के साथ मिश्रित होने का लम्बा इतिहास है। इसका एक उदाहरण केन्द्रीय पंजाब में सरगोधा में बोली जाने वाली एक प्रकार की पंजाबी भाषा है।

7.4.2 संजातीय समूह

1990 के दशक के मध्य के वर्षों में पाकिस्तान का संजातीय संघटन कम से कम बड़े समूहों मे जनसंख्या के लगभग भाषायी वितरण के अनुरूप ही था। 59.1 प्रतिशत पाकिस्तानी स्वयं को पंजाबी, 12.1 प्रतिशत सिंधी, 7.7 प्रतिशत मुहाजिर, 4.3 प्रतिशत बलूच तथा 3 प्रतिशत अन्य संजातीय समूहों के सदस्य मानते हैं। प्रत्येक समूह अपने गृहक्षेत्र पर प्राथमिक रूप से ध्यान केन्द्रित करता है जैसे अधिकांश मुहाजिर शहरी सिंध के क्षेत्र में रहते हैं।

अधिकांश पंजाबी समूहों का संबंध इस्लाम से पहले जाट तथा राजपूत जातियों से है। अन्य पंजाबी अरब पारस, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तथा कश्मीर से हैं। इस प्रकार से पंजाबी का अलग-अलग उद्भव है तथापि इन समूहों ने सामजस्यपूर्ण संजातीय समूह का रूप लिया है जिसने कृषि तथा रक्षा पर ऐतिहासिक रूप से आधिपत्य स्थापित किया है।

पंजाबी सैनिक तथा सिविल सेवा के उच्च पदों पर आसीन हैं तथा अधिकांशत: केन्द्रीय सरकार को चलाने में उनका योगदान है। इस स्थिति का कई पख्तु तथा बलूच और विशेषकर सिंधी समुदायों ने विरोध किया है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व मिला है।

ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान पंजाब के दक्षिण में स्थित सिंध बम्बई का उपेक्षित भीतरी प्रदेश था। प्रमुख जमीदारों (बाडेरा) के छोटे समूह का यह समाज था। शोषित काश्तकार किसानों, जिनकी संख्या अधिक थी, को दासता झेलनी पड़ती थी। स्वतंत्रता के समय इस प्रान्त में धन तथा निर्धनता के दो छोर विद्यमान थे।

विभाजन के बाद के वर्षों में सिंध प्रान्त में उल्लेखनीय उथल-पुथल हुई। लाखों हिन्दू तथा सिक्ख भारत चले गए और उनके स्थान पर लगभग 70 लाख मुहाजिर आ गए जिन्होंने प्रान्त के व्यावसायिक जीवन में सुशिक्षित हिन्दुओं तथा सिक्खों की जगह ले ली। बाद में मुहाजिरों ने शरणार्थी जन आंदोलन (मुहाजिर कौमी महज-एम क्यू एम) को राजनीतिक आधार उपलब्ध कराया। जैसे-जैसे कराची की मुहाजिर शहर के रूप में पहचान बनी तो सिंध के अन्य शहर-थट्टा, हैदराबाद तथा लरकाना, सिंधी विरोध के मुख्यालय बन गए।

उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त की पहचान विश्व के सबसे बड़े जनजातीय समूह, पश्तुन के रूप में की जाती है। वे बलूचिस्तान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान का प्रमुख समूह हैं। भारतीय उप-महाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के समय पर फ्रंटीयर कांग्रेस, जोकि खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में अत्यंत सक्रिय थी, ने पश्तूनिस्तान के अलग राज्य के गठन की मांग की। यह मांग न माने जाने पर यह क्षेत्र पाकिस्तानी राज्य का हिस्सा बना परन्तु इसने पश्तुन आंदोलन की नींव रखी।

1980 के दशक से कई पश्तुन पुलिस, सिविल सेवा तथा सेना में शामिल हुए हैं तथा देश के यातायात नेटवर्क पर इनका आधिपत्य है। उन्हें पाकिस्तान की राजनीतिक संरचना में प्रतिनिधित्व भी मिला है जिससे कुछ हद तक पश्तुन आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्र का अन्य संजातीय अल्पसंख्यक समूह है - बलूची। चार प्रमुख समूहों मैरिक, बुगलिस, बिजोनजोर तथा मोंगल में वर्गीकृत बलूची कुल मिलाकर जनजातीय और नाटीय समुदाय है। यद्यपि इनकी जनसंख्या कम है तथापि बलूची समुदाय ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखी है। उनमें भाषा प्रमुख संयोजक कड़ी रही है। पश्तुनों की ही भांति बलूची समुदाय को पाकिस्तान में शामिल होने पर विरोध था। स्वायतता के लिए चलाए गए बलूच आंदोलन ने 1958-69 के दौरान तथा 1973 के बाद भी हिंसात्मक रूप ले लिया। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान की संघीय संरचना में ही स्वायतता की मांग की। आज उनकी प्रमुख समस्या है - पंजाबी वर्चस्व के समक्ष अपनी अलग "बलूच" पहचान को सुरक्षित रखना।

मुहाजिर मूलत: उत्तर भारत के उर्दू भाषी लोग हैं जो विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। यह लघु समूह प्रमुखत: सिंध, विशेषकर कराची के शहरी वर्ग के रूप में बसा है। भारत के साथ पहचान जुड़े होने के कारण आज भी इन्हें पाकिस्तानी समाज में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी ओर, सिंधी उन्हें अपना प्रमुख प्रतियोगी मानते हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं।

1984 में अलताफ़ हुसैन की अध्यक्षता में मुहाजिर कौमी आंदोलन की शुरूआत हुई। यह आंदोलन है जिससे उनकी संजातीय जागरूकता की अभिव्यक्ति होती है और जिससे उनकी संजातीय शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया गया।

अहमदिया को उनकी विशिष्ट धार्मिक मान्यताओं, जिनके कारण पाकिस्तान सरकार ने इन्हें गैर-मुस्लिम घोषित कर रखा है, के मद्देनजर पाकिस्तान में अलग संजातीय अल्पसंख्यक समूह के रूप में माना जाता है। वे पाकिस्तान की जनसंख्या का 0.12 प्रतिशत है तथा अधिकांशत: पंजाब में बसे हैं।

औपनिवेशिक काल में अहमदिया नौकरशाही तथा सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। जब अहमदियों ने अपने पंथ को बढ़ावा देने का प्रयास किया तो रूढ़िवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया जिन्हें अहमदियों की विचारधारा से सख्त ऐतराज था। पचास के दशक में अहमदियों के विरोध में हिंसात्मक विद्रोह हुए। धार्मिक नेताओं ने बार-बार इनका विरोध किया तथा सरकार ने भी इन्हें प्रताड़ित किया है। इस प्रकार से, अहमदिया अपनी ही जन्मभूमि पर अजनबी हैं तथा अलग-थलग समुदाय हैं।

पाकिस्तान में संजातीय अल्पसंख्यकों द्वारा विभिन्न रूपों तथा दिशाओं में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास राजनीतिक विकास की विशेषता रही है। इस प्रकार से संजातीयता पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में अस्थिरता लाने वाला प्रमुख कारक रही है। अल्संख्यक संजातीय समुदाय बहुसंख्यक पंजाबी समूहों के विरूद्ध संघर्ष करते रहे हैं। संजातीय अल्पसंख्यक समूहों की समस्याएँ अपनी पहचान सुरक्षित रखने तथा बराबरी के आधार पर सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की रही हैं।

7.4.3 धर्म

पाकिस्तान के लगभग 97 प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं जिनमें से 77 प्रतिशत सुन्नी तथा 20 प्रतिशत शिया हैं जबकि अन्य 3 प्रतिशत जनसंख्या बराबर रूप से ईसाई तथा अन्य धर्मों की है।

दक्षिणी एशियाई उप-महाद्वीप में इस्लाम का प्रादुर्भाव आठवीं शताब्दी में घुमक्कड़ सूफी साधुओं-पीरों के आगमन के साथ हुआ। जिन क्षेत्रों में इस्लाम सूफियों द्वारा लाया गया, वहाँ पर भी इस्लाम काफी हद तक इस्लाम पूर्व के प्रभावों के साथ मिश्रित हो गया जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे धर्म का उदय हुआ जो अरब विश्व की तुलना में परम्परागत दृष्टि से अधिक लचीला था।

मुस्लिम कवि एवं दार्शनिक सर मौहम्मद इकबाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग को संबोधित करते हुए उप-महाद्वीप में मुस्लिम राज्य बनाने के विचार का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव का आशय पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र के चार प्रान्तों से था, जो 1971 के बाद पाकिस्तान का क्षेत्र बना। इकबाल के विचार ने "द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त" को मूर्त रूप दिया - विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक रीतिरिवाजों, संस्कृतियों तथा सामाजिक लोकनीतियों के साथ धर्म के आधार पर (इस्लाम तथा हिन्दू) उप-महाद्वीप में दो अलग राष्ट्रों का होना।

इस प्रकार से इस्लाम अलग राष्ट्र के सृजन तथा एकरूपीकरण का आधार था परन्तु इससे सरकार के मॉडल के रूप में कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती थी। मौहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की संविधान सभा के अपने प्रारम्भिक भाषण में धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता की बात कही परन्तु मुस्लिम बहुल राज्य के इस परिप्रेक्ष्य में, जिसमें विकास में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बराबर की हिस्सेदारी होगी, इस पर स्वतंत्रता के बाद ही सवालिया निशान लग गए। 1970 के दशक तक भी चर्चा जारी रही - अहमदियों के अधिकारों, धार्मिक सम्बद्धता दर्शाने वाले पहचान पत्र जारी करने तथा इस्लाम को व्यक्तिगत स्तर पर अपनाने में सरकार के हस्तक्षेप पर विवाद चलता रहा।

बोध प्रश्न 2

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) पाकिस्तान की भाषायी संरचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

.....

.....

.....

2) "अहमदिया" कौन हैं?

.....

.....

.....

7.5 सारांश

स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान को विरासत में प्रमुखत: कृषि अर्थव्यवस्था, कमजोर आधारभूत ढांचा तथा सीमित मानव संसाधन की प्राप्ति हुई। तब से लेकर पाकिस्तान के विकास का रिकार्ड असमान रहा है। प्रारम्भिक वर्षों (1947-58) के दौरान आर्थिक विकास की गति कम रही जबकि 1960 के दशक में ज़बरदस्त विकास हुआ। 1970 के दशक में इसमें धीमापन आया जबकि 80 के दशक में इसने फिर गति पकड़ ली। 90 के अनुवर्ती दशक में फिर इसमें सुस्ती आई। देश के लिए यह दशक खोए हुए अवसर के समान रहा। नई सहस्त्राब्दि के पहले दो वर्षों में पाकिस्तान की वृद्धि

दर सर्वाधिक धीमी गति के ऐतिहासिक रिकार्ड पर पहुंच गईं जबकि तीसरे वर्ष में इसमें फिर से प्रगति हुई है। इस प्रकार से विकास दर को बनाए रखने में अनिश्चितता रही है।

व्यापक रूप से यह माना जाता है कि पाकिस्तान के सामाजिक विकास सूचक देश के आर्थिक विकास तथा संरचनात्मक परिवर्तन की तुलना में अत्यधिक कम रहे हैं।

पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या ने इस्लाम अपनाया है तथापि संजातीय अल्पसंख्यकों में वृहत अन्तर तथा पाकिस्तान के विकास में उनकी तुलनात्मक उपेक्षा की भावना के मद्देनजर धर्म जोड़ने वाले पर्याप्त कड़ी नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अक्तूबर, 2002 में सैनिक सरकार ने राष्ट्रीय चुनाव कराए। लोकतांत्रिक कुशासन की पूर्ववर्ती घटनाओं के मद्देनजर यह उम्मीद करना अभी जल्दी होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्वयं को टिकाए रख सकेगी।

7.6 शब्दावली

सकल घरेलू उत्पाद (GDP): यह देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP): यह विदेश से प्राप्त आय को कम करके देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग है।

वित्तीय घाटा: यह सरकार की कुल आय तथा व्यय का अन्तर है । इसे आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

मुहाजिर: ये उर्दू भाषी लोग हैं जो मूलत: उत्तर भारत के रहने वाले हैं तथा जिन्होंने विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान जाने का विकल्प चुना। यह लोगों का छोटा सा समूह है जो प्रमुखत: सिंध प्रान्त में बसे हैं। ये विशेषकर कराची के शहरी वर्ग के रूप में स्थित हैं।

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

एस० अकबद ज़ैदी (1999), *इश्यूज़ इन पाकिस्तान्स इकोनोमी,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड ।

इशरत हुसैन (1999), *पाकिस्तान: द इकोनोमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड ।

रमाकान्त, एवं अन्य, (2001) *कॉन्टेम्पोरेरी पाकिस्तान : ट्रैन्ड्स एंड इश्यूज़,* (खण्ड-। एवं ।।), कलिंगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली ।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) जुल्फीकार अली भुट्टो ने 1970 के दशक में पाकिस्तान में भारी उद्योग की नींव रखी ।

2) पूर्वी पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने, 1970 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में तेल संकट, जिन्सों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, जलवायु संबंधी कारणों, विषाणु रोगों तथा उर्वरकों की कमी के कारण कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कारण भी विकास की गति धीमी रही क्योंकि योग्य प्रबंधक तथा पूंजी देश से बाहर चली गई।

3) सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान विकास नीति में फेरबदल किया गया। निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को विनियमित तथा उदारीकृत किया गया और निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। घरेलू मांग में हुई तीव्र वृद्धि तथा भुट्टो शासन में औद्योगिक निवेश से प्राप्त आय से उच्च औद्योगिक विकास हुआ।

बोध प्रश्न 2

1) कृपया उप-भाग 7.4.1 देखें ।

2) अहमदिया के धार्मिक विचार इस्लाम से भिन्न हैं। यद्यपि औपनिवेशिक समय में वे समाज के उच्च पदों पर आसीन थे, परन्तु अब उन्हें गैर-मुस्लिम घोषित किया जा चुका है तथा उनका धार्मिक नेताओं व सरकार दोनों ने विरोध किया है।